सांध्य दैनिक
RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 86 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 08 जनवरी 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

कड़ाके की ठंड : रायपुर में 6.6 डिग्री रात का पारा

रायपुर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों के कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। ठंड के कारण राज्य के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है, और उत्तरी हिस्सों में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अंबिकापुर में रात का तापमान 3.3 डिग्री पहुंच गया है। वहीं रायपुर में 6.6 डिग्री, पेंड्रा में 7.6 डिग्री, दुर्ग और राजनांदगांव में 8 डिग्री, और जगदलपुर में 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री (जगदलपुर) और सबसे न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री (अंबिकापुर) दर्ज किया गया।

नाबालिग शूटर से रेप का आरोपी नेशनल कोच सस्पेंड

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद की एक नाबालिग शूटर ने कोच पर रेप का आरोप लगाया है। शूटर का कहना है कि कोच ने उसकी परफॉर्मेंस पर बात करने के बहाने फरीदाबाद की फाइव स्टार होटल के रूम में बुलाकर उसके साथ रेप किया। इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसका करियर खत्म करने की भी धमकी दी। नाबालिग करीब 20 दिनों तक सदमे में रही। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी घटना बताई। 6 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फरीदाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में होटल के स्टाफसे भी पूछताछ की जा रही है। मामले में संज्ञान लेते हुए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होग अंकुश सस्पेंड रहेंगे।

जल जीवन मिशन के तहत 11 ग्राम पंचायतो को प्रशिक्षण

जीपीएम। जल जीवन मिशन के तहत पेण्ड्रा विकास खण्ड के 11 ग्राम पंचायत के सरपंचो, सचिवों, पंप ऑपरेटरों, पंचों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यो को नल जल संधारण का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें ग्राम पंचायत अमरपुर, अड़भार, बचरवार, पतगंवा, कुडकई, गिरारी, झाबर, नवागांव, बसंतपुर, सकोला एवं कोटमी कला शामिल हैं। प्रशिक्षण में ट्रेनर्स द्वारा जलापूर्ति की आवश्यकता, एफएचटीसी के लाभ, हर घर जल प्रमाणीकरण, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया।

विकसित भारत जीरामजी पर बोले सीएम साय- मनरेगा से बेहतर है यह योजना

श्रमिकों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार, भुगतान में देरी पर मिलेगी अतिरिक्त राशि

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) को लेकर कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना मनरेगा से बेहतर है। वीबीजीरामजी योजना को मनरेगा से ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। इस योजना में न सिर्फ काम के दिन बढ़ाए गए हैं बल्कि मजदूरी भुगतान को लेकर सख्त समय-सीमा तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में जहां सालाना 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, वहीं जी राम जी योजना में यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों को 25 दिन अतिरिक्त काम मिलेगा और आमदनी में सीधा इजाफा होगा। सीएम साय ने कहा कि योजना की सबसे खास बात यह है कि भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जहां मजदूरी एक सप्ताह के भीतर खाते में पहुंचाने का प्रावधान रखा गया है। नहीं होने पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

विपक्ष का विरोध

मनरेगा और जी राम जी को लेकर विपक्षी दलों का विरोध भी जारी है। जब से योजना से संबंधित बिल पास किया गया तब से सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई योजना को दिखावटी बदलाव करार देते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जहां पहले पूरी राशि केंद्र सरकार देती थी, अब उसमें 40 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी, ऐसे में योजना के संचालन पर संशय है।

देर से भुगतान पर मिलेगा अतिरिक्त पैसा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि, नई योजना में मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में श्रमिकों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भुगतान में अनावश्यक विलंब पर अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक अनिश्चितता कम होगी।

खेती सीजन में रहेगी बंद

सीएम ने कहा यह योजना पूरे साल नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जब किसानों के पास खेतों में भरपूर काम होगा, खासकर धान कटाई के मौसम में, तब जी राम जी योजना को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। साल में करीब दो महीने यह योजना लागू नहीं होगी, ताकि किसान और खेतिहर मजदूर कृषि कार्यों पर ध्यान दे सकें।

जानिए क्या है जीरामजी योजना

जीरामजी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) अधिनियम 2025 के तहत लाई गई नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसे मनरेगा के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इसमें प्रति परिवार 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार, सड़क, जल और जलवायु से जुड़े बुनियादी ढांचे पर फोकस, पीएम गति शक्ति योजना से समन्वय और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था शामिल है। हालांकि इसमें कृषि सीजन के दौरान 60 दिनों तक कार्य विराम और फंडिंग व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य 2047 तक ग्रामीण आय और विकास को नई दिशा देना है।

पुनर्वासितों ने देखा बस्तर का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक वैभव

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। हिंसा का अंधेरा छोड़कर शांति और विकास की 'नुवा बाट' (नई राह) चुनने वाले पुनर्वासितों बस्तर का सांस्कृतिक-ऐतिहासिक वैभव देखा। जगदलपुर स्थित पुनर्वास केंद्र में निवासरत पुर्नवासितों को बस्तर के प्रमुख दर्शनीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया गया।

भ्रमण की शुरुआत बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन से हुई। मंदिर में पूजा-अर्चना कर सभी ने अपने उज्ज्वल और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना की। इसके पश्चात दलपत सागर और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के केंद्र 'दशहरा पसरा' का अवलोकन कराया गया, जहां उन्हें बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत की जानकारी दी गई। दिन का सबसे रोमांचक पड़ाव विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात रहा। झरने गर्जना ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

'नुवा बाट' के तहत आयोजित यह भ्रमण महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इससे पुर्नवासितों को यह विश्वास हुआ कि हिंसा छोड़कर समाज के साथ कदमताल करने में ही जीवन की वास्तविक खुशी और उन्नति निहित है। खुली हवा में सांस लेते हुए और बस्तर की बदलती, विकासोन्मुख तस्वीर को अपनी आंखों से देखकर पुर्नवासितों ने महसूस किया कि शांति का मार्ग ही सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है।

कोयला खदान में ब्लास्टिंग से किसान की मौत

■ एसईसीएल के दीपका खदान में हादसा, सिर पर गिरा पत्थर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दीपका खदान में बड़ा हादसा हो गया। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान उछला पत्थर एक किसान के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर शव रखकर रात 11 बजे तक प्रदर्शन करते रहे। मौके पर पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था।

बाद में कंपनी ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ।मृतक की पहचान रेकी गांव निवासी लखन लाल पटेल (60) के रूप में हुई है। बेटे अनिल कुमार ने बताया कि पिता हरदीबाजार में अपने साढ़ू भाई के यहां गए थे। वहां से पैदल लौटते समय यह हादसा हुआ। ब्लास्टिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं एसईसीएल प्रबंधन ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही कहा कि एरिया प्रबंधन मामले की जांच कर रहा है।

बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-7 में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह स्पार्कल-25 का आयोजन

भिलाई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-7 ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 6 जनवरी को विद्यालय परिसर स्थित सभागार में रजत जयंती पर 25वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह स्पार्कल-25 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की 25 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता, निरंतर प्रगति तथा सर्वांगीण शिक्षा की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक अजय कुमार चक्रवर्ती रहे व विशिष्ठ अतिथि के तौर पर मुख्य महाप्रबंधक (नगर प्रशासन एवं सीएसआर) उत्पल दत्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में महाप्रबंधक (टीएसडी) एबी श्रीनिवासन, महाप्रबंधक (शिक्षा)शिखा दुबे, पीटीए सदस्य, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, अभिभावकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

अपार आईडी निर्माण में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़

■ अपार से विद्यार्थियों को मिल रही स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई अपार व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

7 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में

अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

31 जनवरी तक पूरा करने भारत सरकार का निर्देश

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- तो क्या चूहों के लिए बिल्ली को ले आएं?

नई दिल्ली ए.। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को फिर से सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा जानवरों से होने वाले खतरों और उन्हें नियंत्रित करने में नागरिक अधिकारियों की कथित कमियों को उजागर करने वाली याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया।

दरअसल सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दलील देते हुए कहा, 'दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। कुत्तों को अचानक हटाने से क्या होता है? चूहों की आबादी बढ़ जाती है। कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं।' उनकी इस दलील पर न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने टिप्पणी की, 'क्या इसका आपस में कोई संबंध है? हमें बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे चूहों की दुश्मन हैं।' इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि हमने गली के हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया है।

लाखों नागरिक संदिग्ध!

गुस्ताखी माफ - दीपक रंजन दास

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण क्या शुरु हुआ, देश के लाखों लोग संदिग्ध हो गए। कैसे? इसका किसी के पास जवाब नहीं। दरअसल, यह गलती भारत के निर्वाचन आयोग की है कि उसने आंकड़ों को कुछ इसी तरह से पेश करना शुरू किया। एक बार में जिसका नाम आ गया तो आ गया। जिसका नहीं आया वो संदिग्ध। हालांकि, उसे अपनी पात्रता साबित करने का दूसरा मौका भी दिया जाता है पर तब तक वह संदिग्ध ही बना रहता है। दरअसल, यह शब्दों के गलत चयन का मामला है। यह गलती भी शायद जानबूझकर की गई है। कुछ क्या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियें भर गए हैं। इसलिए आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए जैसे ही कोई कहता है कि लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर तो लोग इसपर यकीन भी कर लेते हैं। उनके जेहन में एक बार भी यह बात नहीं आती कि हो सकता है प्रक्रियागत त्रुटि या सूचियों की असंबद्धता या अपूर्णता इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। निर्वाचन आयोग खुद इसका दूसरा मौका देता है। छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल यही चल रहा है। यहां अभी पहली सूची आई है। इसमें ऐसे लोगों के नाम भी गायब मिले हैं जो न केवल जन्म से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं बल्कि जिनकी पूरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई है। जिनका विवाह भी यहीं हुआ और जो अपने बाल बच्चों के साथ यहीं जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अब ये एक फार्म और भरेंगे जिसमें कुछ और विकल्प दिये गये हैं। यह एक प्रक्रियागत कार्य है जिसमें त्रुटि संशोधन कर एक साफ-सुथरी मतदाता सूची बनाने का अभिप्राय झलकता है। पर आयोग सनसनी का आनंद ले रहा है। अखबार भी उसका साथ दे रहे हैं। 15 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर, 15 लाख संदिग्धों के नाम, जैसे शीर्षक लोगों को आनंदित कर रहे हैं। कायदे से पुनरीक्षित सूची के आने तक संयम से काम लिया जाना चाहिए। जिनके नाम पहली सूची में नहीं है, वह सरकारी लापरवाही का नतीजा है। इसका दोष मतदाता पर कैसे मढ़ा जा सकता है? उसे संदिग्ध कैसे कहा जा सकता है?

रायपुर में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

रायपुर। रायपुर के राजेंद्र नगर थाने इलाके में एक 18 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान अमलीडीह मारुति रेजिडेंसी निवासी हनीफा उर्फ अनिमा पटेल (18), पिता महेंद्र पटेल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती के पिता मंदिर हसौद थाना ने एनडीपीएस एक्ट के पुराने मामले में आरोपी है। पुलिस ने आरोपी के खिलावारंट भी जारी किया। लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। आशंका जताई जा रही है कि इस डर से बेटी घबरा गई और उसने घर पर फांसी के फंदे में झूलकर सुसाइड कर लिया। बाद में फोन के माध्यम से युवती की मां को इस घटना की सूचना मिली। पुलिस ने लाश को मर्चुरी भेज दिया है। इस घटना के बाद परिवार मातम में है।

संपादकीय

एक बेतुका आदेश

शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराना अनुचित

हाल के दिनों में देश की शीर्ष अदालत से लेकर आम विमर्श तक में आवारा कुत्तों का मामला सुर्खियों में रहा है। इस संवेदनशील, जटिल व विवादास्पद मुद्दे से जुड़े कई तरह के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बिहार के एक नगर निगम के बेतुके फरमान को लेकर आलोचना की जा रही है। यह निर्णय न केवल बेतुका है बल्कि हास्यास्पद भी है। बिहार के सासाराम के नगर निगम ने शिक्षकों से सड़कों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की गिनती करने को कहा है। दरअसल, अदालत के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों की इस बाबत जवाबदेही तय की गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों व गिरते परीक्षा परिणाम के बावजूद शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हर छोटे-बड़े सरकारी अभियान में शिक्षकों की जिम्मेदारी लगाना प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करता है। कभी जनगणना, कभी चुनावी ड्यूटी तो कभी आपदा सर्वेक्षण, और अब कुत्तों की गिनती का बेतुका काम शिक्षकों के जिम्मे लगा दिया गया है। दरअसल, बिहार के शिक्षक विषम परिस्थितियों के चलते पहले ही अत्यधिक दबाव में हैं। जिसके कारण वे शैक्षणिक जिम्मेदारियों व गैर-शिक्षण दायित्वों के लगातार बढ़ते बोझ के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हर इस तरह का व्यवधान कक्षा के समय, पाठ योजना और छात्रों की सहभागिता को गहरे तक प्रभावित करता है। निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा बच्चे के विकास की नींव रखती है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक रहता है। वर्षों से पेश की जा रही एएसईआर रिपोर्टों में कई बार उजागर किया गया है कि बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम देश में सबसे कमजोर रहा है। जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है।

“ खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के आदेश की तार्किकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे।

ऐसे में जब पहले ही बिहार के स्कूलों का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है तो शिक्षकों को एक और गैर-शैक्षणिक कार्य के लिये कक्षाओं से बाहर निकालना, निस्संदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम ही कहा जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि यह आदेश कई वास्तविक खतरों से भरा है। आवारा कुत्तों की गिनती करना शिक्षण के कागजी कार्य के समान सहज नहीं है। निश्चित रूप से अनेक शिक्षक ऐसे होंगे जो कुत्तों से डरते भी होंगे। खासकर शिक्षिकाओं के लिये यह कार्य खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ लोग इस गणना प्रक्रिया में वास्तविक खतरे का सामना भी कर सकते हैं। इस बात का संकेत शीर्ष अदालत की टिप्पणी में भी मिलता है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी कुत्ते के मन को पढ़ना या यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई जानवर कब आक्रामक हो जाएगा। निश्चित रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, उनकी सुरक्षा के लिये भी चुनौती होगी। खासकर तब जब आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं और रेबीज से होने वाली जीवन क्षति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम के आदेश की तार्किकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण और जन सुरक्षा उपायों को लागू करने में नगरपालिकाओं की विफलता पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद एक स्थानीय निकाय ने अपनी मूल जिम्मेदारी शिक्षकों पर थोपकर इसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से यह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। निर्विवाद रूप से इस बेतुके आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जरूरत है। सही मायनों में नगरपालिका के अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए और शिक्षकों को भी अपना काम करने की आजादी दी जानी चाहिए। यह समस्या केवल शिक्षकों की ही नहीं है बल्कि यह हमारे नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्यत्र काम सौंपना, कहीं न कहीं छात्रों और छात्राओं को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करने जैसा भी है।

प्रगति पोर्टलः भारत की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने वाला एक गेम चेंजर

आर.के जैन

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना आज़ादी के बाद शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई के लिए उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस विशेष रेल कॉरिडोर तैयार करना है। इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल तेज़, सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत वाली लॉजिस्टिक सेवाएं देकर माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दोबारा बढ़ाना चाहती है। साथ ही, इस परियोजना से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा। करीब 1.2 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत और 2843 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के दो मुख्य हिस्से हैं।

पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(ईडीएफसी): यह 1337 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक जाता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से होकर गुजरता है।

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी): यह 1506 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक फैला हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का मार्ग 7 राज्यों और 56 जिलों से होकर गुजरता है। यह जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों और क्रीक इलाकों से भी होकर जाता है, जिससे इस परियोजना का निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन कई बाधाओं के कारण कई वर्षों तक काम की गति धीमी रही। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थीं:

ज़ लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, जिसमें अवैध कब्जे और बने हुए ढांचों को हटाना शामिल था। ज़ वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों, पेड़ों की कटाई और क्रीक (नाले) पार करने से जुड़े कानूनी अनुमतियां प्राप्त करना। 900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण, जिनके लिए संयुक्त नक्शा स्वीकृति और रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था। हाई टेंशन बिजली लाइनों, गैस और तेल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना। रक्षा विभाग, एनएचएआई, राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों, सिंचाई विभाग से नहर पार करने की अनुमति और मिट्टी उधार लेने की स्वीकृति। कोविड के बाद ठेकेदारों पर पड़ा आर्थिक दबाव, जिससे नकदी की कमी हुई। निर्माण के लिए बिना किसी बाधा वाली भूमि उपलब्ध न होने से कार्य समय-सारिणी पर गंभीर असर पड़ा और परियोजना पर संभावित दावों का खतरा भी बढ़ गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुरू किया गया प्रगति पोर्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से डीएफसी के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं को पूरे दस्तावेज़ों के साथ अपलोड किया। प्रगति पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही थी। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों को यह साफ़ पता था कि कार्य की प्रगति पर सबसे ऊंचे स्तर पर, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी, निगरानी की जा रही है। जो मुद्दे वर्षों तक लगातार प्रयासों के बावजूद अटके रहे थे, वे कुछ ही हफ्तों में, और कई मामलों में तो कुछ दिनों के भीतर ही, सुलझा लिए गए। जहाँ तुरंत समाधान संभव नहीं था, वहाँ विभागों ने निश्चित समय-सीमा तय की और उसका सख्ती से पालन किया गया।

प्रगति पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी मंच के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से: परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी संभव हुई, समस्याओं को एक साथ कई स्तरों तक तुरंत पहुँचाया जा सका, एक ही मंच से मंत्रालयों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो पाया डीएफसी परियोजना में भी इसी तरह की एक आंतरिक निगरानी व्यवस्था लागू की गई। बड़े ठेकों की साप्ताहिक समीक्षा, नियमित स्थल निरीक्षण और तय किए गए लक्ष्यों की लगातार निगरानी सामान्य प्रक्रिया बन गई। चूंकि पोर्टल पर डाली गई सभी समय-सीमाएं दर्ज रहती थीं, इससे परियोजना टीम के भीतर अपने वादों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी मज़बूत हुई।

परियोजना क्रियान्वयन पर स्पष्ट प्रभाव

जटिल समस्याओं के तेज़ समाधान से निर्माण कार्य में उल्लेखनीय तेजी आई और बिना बाधा वाली भूमि समय पर उपलब्ध न होने से होने वाले संभावित दावों से संगठन को सुरक्षा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रगति पोर्टल ने रोज़मर्रा की परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही को शामिल करके पूरे शासन तंत्र की कार्यसंस्कृति को ही बदल दिया। प्रगति पोर्टल आज प्रभावी डिजिटल शासन का एक जीवंत उदाहरण है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी विशाल परियोजना, जो कई राज्यों, विभागों और नियामक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, के लिए प्रगति केवल एक निगरानी उपकरण नहीं रहा, बल्कि बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ।

तेज़ फैसले सुनिश्चित करके, विभागों के बीच टकराव कम करके और हर स्तर पर जवाबदेही तय करके, प्रगति पोर्टल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को सफल और समय पर पूरा करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। साथ ही, इसने भारत की आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया है।

(लेखक डीएफसीसीआईएल के पूर्व एमडी हैं)

कर वसूली के साथ जरूरी सुविधाएं भी तो मिलें

राकेश गांधी

देश में दोहरी कर प्रणाली आम नागरिक के लिए असंतोष का कारण बन रही है। पहले वेतन पर आयकर और फिर खर्च पर जीएसटी। यह भी कि सत्ताधारी लोग सुविधाओं में जीते हैं और आम नागरिक मूल जरूरतों के लिए जूझते हैं। कर ढांचा न्याय व समानता पर आधारित होना चाहिए।

भारत का आम नागरिक आज कर व्यवस्था को लेकर गहरे असमंजस में है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसके लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। राष्ट्र निर्माण का दायित्व निभाने वाला यही वर्ग सबसे अधिक दबाव में है। इस असंतोष की जड़ में वह संरचना है जिसे आम भाषा में दोहरी कर व्यवस्था कहा जाता है। कागजों में यह व्यवस्था तर्कसंगत दिखाई देती है। लेकिन धरातल पर यही व्यवस्था नागरिक की जेब और विश्वास दोनों पर चोट करती है।

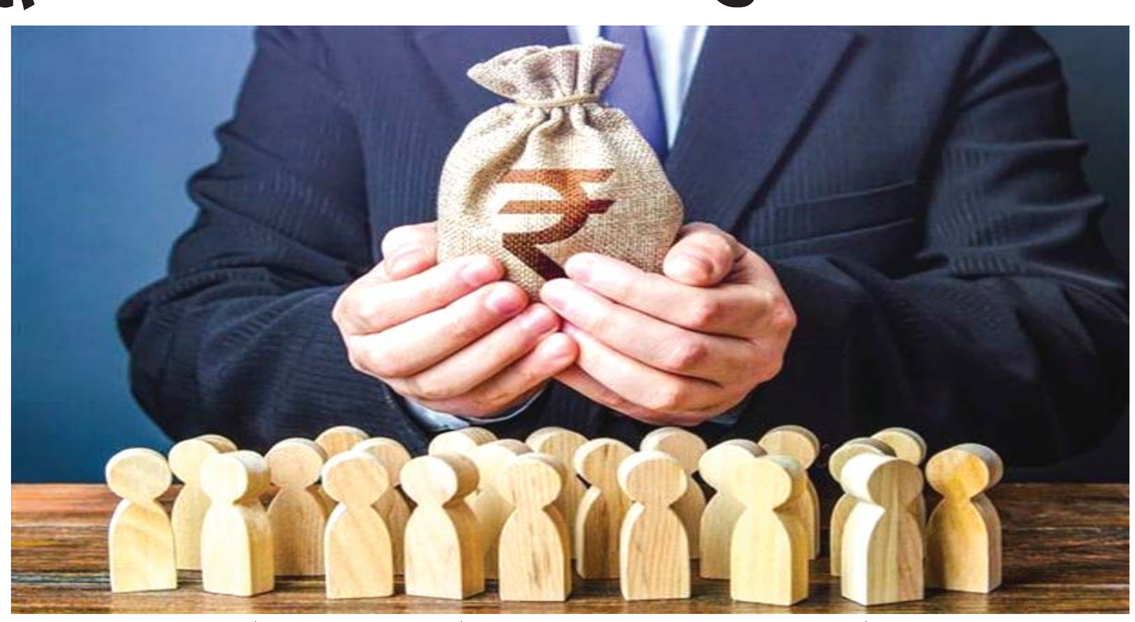

एक नागरिक महीने भर श्रम करता है। वेतन पाता है। उसी वेतन पर वह आयकर देता है। लेकिन कर यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कर कटने के बाद बची हुई आय से जब वह दवा खरीदता है। भोजन करता है। ईंधन भरवाता है। बच्चों की शिक्षा या किसी सेवा का भुगतान करता है तो हर कदम पर उसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देना पड़ता है। सरकार का तर्क है कि आयकर कमाने पर है और जीएसटी व्यय पर। तकनीकी रूप से यह बात सही हो सकती है। लेकिन आम नागरिक के लिए आय का स्रोत एक ही होता है और खर्च भी उसी सीमित राशि से होता है। पैसा वही रहता है। केवल कर के नाम बदल जाते हैं। बोझ कम नहीं होता।

यह पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब नागरिक सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों की जीवनशैली देखता है। प्रश्न तब केवल कानूनी नहीं रह जाता बल्कि नैतिक हो जाता है। आम नागरिक पूछता है कि जब उसने अपनी आय पर कर चुका दिया तो जीवन की हर जरूरत पर दोबारा कर क्यों? लोकतंत्र में इस प्रश्न को असंगत नहीं कहा जा सकता।

कानूनी सच्चाई यह है कि सांसदों और विधायकों का वेतन आयकर के दायरे में आता है और वे कर देते हैं। लेकिन असमानता वेतन में नहीं बल्कि सुविधाओं में है। सरकारी आवास, बिजली- पानी, यात्रा, चिकित्सा, सुरक्षा व स्टाफजैसी सभी सुविधाओं का बाजार मूल्य अत्यंत ऊंचा है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह या तो मुफ्त मिलता है या नाममात्र शुल्क पर। वहीं आम नागरिक इन्हीं सुविधाओं के लिए अपनी कर देने के बाद बची आय से पूरा भुगतान करता है। कागजों में कर समान है लेकिन जीवन की वास्तविक लागत में गहरी खाई दिखती है। इस असंतुलन को और उजागर करती है उद्घाटन और दौरों की संस्कृति। मामूली से कार्यक्रम के लिए भी नेता विमान या हेलिकॉप्टर से पहुंचते हैं। सुरक्षा के नाम पर लंबे काफिले चलते हैं। सड़कें रोकी जाती हैं। प्रशासनिक तंत्र उसी आयोजन में झोंक दिया जाता है। इन सब पर होने वाला खर्च लाखों और कई बार करोड़ों में होता है। यह खर्च देश के राजस्व से होता है। यानी उसी करदाता के पैसे से जो स्वयं यातायात में फंसा हुआ अपने ईंधन का पूरा मूल्य और कर चुका रहा होता है।

कृषि आय को कर से मुक्त रखने का निर्णय अपने समय में मानवीय और आवश्यक था। खेती जोखिम भरा और मौसम पर निर्भर है। छोटे किसान की आय अस्थिर होती है। लेकिन समय के साथ इस छूट का दुरुपयोग भी बढ़ा। अनेक गैर किसान और प्रभावशाली लोग अपनी आय को कृषि आय दिखाकर टैक्स से बचते रहे। असली किसान तक इस व्यवस्था का कितना लाभ पहुंचा यह आज भी स्पष्ट नहीं। इससे कर व्यवस्था के प्रति अविश्वास और गहराता है।

मूल प्रश्न इससे भी आगे का है। जब नागरिक कर देता है तो बदले में उसे क्या मिलता है। शिक्षा आज भी निजी संस्थानों पर निर्भर है। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं। वृद्धावस्था की सुरक्षा सीमित है। रोजगार अनिश्चित है। कर चुकाने के बाद भी जीवन की बुनियादी जिम्मेदारियां नागरिक को स्वयं उठानी पड़ती हैं। ऐसे में कर राष्ट्र निर्माण की साझेदारी नहीं बल्कि मजबूरी जैसा लगने लगता है।

यही अंतर भारत और डेनमार्क जैसे देशों में दिखाई देता है। वहां कर अधिक है, लेकिन बदले में नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की ठोस गारंटी मिलती है। इसलिए कर वहां बोझ नहीं बनता। भारत में कर दरें कम बताई जाती हैं लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाएं तो मध्यम वर्ग पर वास्तविक बोझ कहीं अधिक दिखाई देता है। सुविधाएं फिर भी सीमित रहती हैं।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह दोहरी कर व्यवस्था न किसी एक दल की देन है और न ही किसी एक सरकार की। यह आजादी के बाद विकसित हुई कर संरचना का परिणाम है। समय बदला। अर्थव्यवस्था बदली। नागरिक की अपेक्षाएं बदलीं। लेकिन कर व्यवस्था का मूल स्वरूप लगभग जस का तस बना रहा। इसलिए आज यह असहज लगने लगी है। यह आरोप का विषय नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। आवश्यकता यह है कि कर सुधार की शुरुआत सत्ता के आचरण से हो। उद्घाटन संस्कृति पर नियंत्रण लगे। हवाई यात्राएं केवल अपरिहार्य स्थितियों में हों। काफिलों का मानकीकरण हो। हर सरकारी दौरे और कार्यक्रम के खर्च का सार्वजनिक विवरण अनिवार्य किया जाए। जब नागरिक देखेगा कि सत्ता स्वयं संयम बरत रही है तब वह कर को बोझ नहीं बल्कि सहभागिता मानेगा।

कर केवल वसूली नहीं बल्कि यह एक सामाजिक समझौता है। नागरिक कहता है कि मैं अपनी मेहनत का हिस्सा दूंगा, क्योंकि राज्य मेरी सामूहिक जिम्मेदारी लेगा। आज नागरिक कर का विरोध नहीं कर रहा। वह कर न्याय की मांग कर रहा है। वह कह रहा है कि मुझसे कर वसूलो, लेकिन पहले यह सिद्ध करो कि सत्ता भी उतनी ही उत्तरदायी और संवेदनशील है जितना एक आम नागरिक को होना पड़ता है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सशक्त मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर- पोषण निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं सूरजपुर की महिलाएं

धनंजय राठौर ,संयुक्त संचालक
प्रदीप कंवर ,सहायक संचालक

आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की नींव सशक्त मानसिकता पर आधारित होती है। दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सूरजपुर जिले की स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने इस सोच को व्यवहार में उतारते हुए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल प्रस्तुत की है। ये महिलाएं न केवल स्वयं सशक्त बन रही हैं, बल्कि जिले की महिलाओं एवं बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पोषण आहार (रेडी-टू-ईट या ऋ्रञ्श्व) निर्माण संयंत्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी इकाइयाँ हैं, जो आंगनवाड़ियों और अन्य योजनाओं के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए पौष्टिक, पहले से तैयार भोजन बनाती हैं, जिसे महिला स्व-सहायता समूहों (स्।त्रह्य) द्वारा चलाया जाता है, जिससे पोषण और महिलाओं का सशक्तिकरण दोनों होता है, जिसमें गेहूं, दालें, और दूध जैसे घटक शामिल होते हैं, जो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्काल उपभोग हेतु तैयार पोषण आहार (रेडी टू ईट) निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। इन संयंत्रों में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक नमकीन दलिया तथा मीठा शक्ति आहार का निर्माण किया जा रहा है, जो विटामिन ‘ए’, विटामिन ‘डी’, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरीडॉक्सिन, फोलिक अम्ल, कोबालामिन, लोह तत्व (आयरन), कैल्शियम एवं जिंक जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है।

जिले प्रशासन द्वारा जिले में कुल 07 पोषण आहार निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए है। यहां वर्तमान में भैयाथान, प्रतापपुर एवं सूरजपुर विकासखंड में तीन संयंत्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इन तीनों संयंत्रों में 32 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से पोषण आहार निर्माण कार्य में संलग्न हैं। निर्मित पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार स्व-सहायता समूहों की महिलाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण में अप्रत्यक्ष किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात है कि पोषण आहार के निर्माण के साथ-साथ उसके वितरण की भी जिम्मेदारी भी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है।

सूरजपुर विकासखंड में 15 स्व-सहायता समूह तथा प्रतापपुर विकासखंड में 13 स्व-सहायता समूह सक्रिय रूप से वितरण कार्य में अपनी भूमिका निभा रही है। इन समूहों के माध्यम से कुल 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार वितरण कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस योजना से महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मानसिक रूप से सशक्त ये महिलाएं अब घरेलू कार्यों के साथ-साथ आजीविका से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। यह पहल न केवल निश्चित रूप से जिले में पोषण स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

धमकी न धौंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस

तिरछी नज़र

हमारी पुरानी कहावत ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ में जितना दम है, उतना आज की दुनिया के किसी घोषणापत्र में नहीं है। फर्क बस इतना है कि पहले लाठी मोटे बांस की होती थी, अब उसके नाम बदल गए हैं— बंदूक, मिसाइल और दादागीरी आज पूरी दुनिया में लाठी वाला मिनटों में भैंस खोलकर ले जाता है और मालिक कागजों में अधिकार ढूंढ़ता रह जाता है। शांति की बातें मंचों पर होती हैं लेकिन बंदूक की नोक से ‘शांति’ शब्द लिखने की कोशिश की जा रही है। शांति तो आज भी प्यार की कलम से आएगी मगर उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं, हिम्मत चाहिए।

पहले कहते थे- घर में रहो, सुरक्षित रहोगे। अब तो घर ही टारगेट बन गया है। दीवारें भी घबराई हुई हैं। चोरों के हौसले ऐसे बुलंद हैं कि दीवार फांद कर नहीं आते, सीधे किवाड़ तोड़ देते हैं। और हम? हम तो बस गिनती करते रह जाते हैं- टीवी गया, जेवर गया, नींद गई, आत्मसम्मान गया। ये आग अब सिर्फ हमारे मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। अब तो एक देश के मुखिया की कुर्सी तक को निगलने चली आई है। जब सबसे ऊंची कुर्सियां हिल रही हैं तो आम आदमी की चारपाई की औकात ही क्या है? ऊपर से नीचे तक बस एक ही संदेश है- जिसकी लाठी, उसी की भैंस। आज के जमाने में भैंस रस्सी से नहीं, डर से बंधी होती है। अब न खूंटा चाहिए, न बाड़, बस एक धमकी और एक हथियार से भैंस दौड़ी चली आती है। डर ऐसी लाठी है कि भैंस तो कब की जा चुकी होती है और हम रस्सी ढूंढ़ते रह जाते हैं।

लाठीधारी दादा लोगों को न डर लगता है, न शर्म आती है। बेशर्मी से हंसते हुए ये डर का फ्री पैकेज देते फिर रहे हैं। इन्हें सिर्फविस्तार चाहिए, कब्जा चाहिए, लूट चाहिए। हाल ये हो गया है कि आदमी से लेकर राष्ट्राध्यक्ष तक न घर में सुरक्षित है, न बाहर। न कुर्सी बची है, न खाट। लड़कियों के अपहरण की खबरें तो सुनी थीं पर एक देश का राष्ट्रपति पत्नी समेत उठा लिया गया तो बताओ आम लोग-लुगाई किस खेत की मूली हैं। जिस देश में ताज भी सुरक्षित नहीं वहां तकिया तो किस हाल में होगा, अंदाजा लग सकता है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाऐं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

अरबन पब्लिक की 69 कंडम सिटी बसों की होगी नीलामी

भिलाई। दुर्ग जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी अंतर्गत 69 कंडम सिटी बसों का मेटल स्क्रेप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से निलामी किया जा रहा है। 69 कंडम सिटी बसों को खरीदने हेतु एमएसटीसी पोर्टल में रजिस्टर्ड बिडर ही नीलामी में भाग ले सकते है। ऑक्शन क्रमांक 25-26/53782 दिनांक 09.01.2026 समय 12:00 बजे से 5:00 बजे तक प्रक्रिया में भाग ले सकते है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

स्कूली बच्चों को दिलायी गयी स्वच्छता की शपथ

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा के एस.एल.आर.एम. सेंटर में स्कूली बच्चों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। बच्चों को स्वच्छता का संदेश देते हुए बताया गया कि सूखा कचरा नीला एवं गीला कचरा हरा डस्टबिन में अलग-अलग रखा जाना चाहिए। निगम का सफाई मित्र घरो से निकले कचरे को एकत्र कर एस.एल.आर.एम. सेंटर तक पहुंचाने का काम करते है। यह भी बताया गया कि स्वच्छता दीदियां किस प्रकार कचरे से पॉलीथिन, प्लास्टिक, धातु और अन्य सामग्रियों को अलग करते हैं। गीला कचरे को मशीन में डालकर खाद बनाने तक की प्रक्रिया को समझाया गया।

अब तक 3,49,069.92 मीट्रिक टन धान खरीदी गई

दुर्ग। राज्य सरकार की सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी नीति के कारण जिले में धान खरीदी और उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव में तेजी आई है। राज्य सरकार के निर्णायक कदम से धान विक्रय की प्रक्रिया सरल हुई है। जिसके तहत अब दिन-रात कभी भी मोबाईल एप तुंहर टोकन के माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन मिलने लगा है। किसानों के लिए यह बड़ी सहुलियत है कि उनके लिए तुंहर टोकन एप अब 24 घंटे उपलब्ध है। अब मोबाईल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नही है। जिले में अब तक 82,486.97 लाख रूपए की लागत से 3,49,069.92 मे. टन धान की खरीदी हो चुकी है। समय पर भुगतान राशि मिलने पर 64437 किसान लाभान्वित हुए हैं।

ग्राम घोराड़ी (भरर) में आबकारी विभाग की कार्यवाही

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त आबकारी सीआर साहू के मार्गदर्शन में 6 जनवरी को ग्राम गस्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग के द्वारा वृत-दुर्ग आंतरिक दक्षिण में अवैध शराब के विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर ग्राम घोराड़ी थाना रानीतराई में आरोपी लोकेश बंजारे पिता दयालु राम निवासी घोराड़ी रानीतराई के कब्जे से 40 पाव प्लेन मदिरा जप्त कर 34 (2) का प्रकरण कायम कर आरोपी को जेल दाखिला कराया गया। उक्त प्रकरण वृत्त प्रभारी अरविन्द साहू के द्वारा विवेचना में लिया गया है। इस प्रकरण में मुख्य आरक्षक संतोष दुबे, ड्राइवर नोहर का विशेष योगदान रहा।

ग्राम पंचायत बासीन में एक साथ मनाया गया रोजगार दिवस और आवास दिवस (ग्रामीण)

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास दिवस का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बासीन में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीईओ बजरंग कुमार दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, उपाध्यक्ष पवन शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं पूर्ण आवासों के हितग्राहियों की सूची का वाचन किया गया तथा हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिन हितग्राहियों ने 90 दिवस के भीतर अथवा अत्यंत शीघ्रता से आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्रामीण सरलता से योजनाओं का लाभ और जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम के दौरान रोजगार दिवस के तहत आजीविका डबरी निर्माण, आजीविका संवर्धन तथा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर भी चर्चा की गई।

'आवास दिवस' के आयोजन से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ेगी, आवास निर्माण में आ रही बाधाओं एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। साथ ही निर्माण सामग्री से जुड़ी समस्याओं के समाधान, सामग्री बैंक की स्थापना एवं पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों के आवास कार्यों को प्राथमिकता देना है।

फ्री ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, श्रीराम रसोई, वेंटिलेटर एंबुलेंस, कंबल बैंक के बाद स्वर्गरथ लोकार्पित

जनहित में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन लगातार दे रहे सौगातें

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपनी जनसेवा की कड़ियों में एक और मोती जड़ दिया है। अब क्षेत्रवासियों को अंतिम संस्कार हेतु वाहन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। विधायक श्री सेन ने बुधवार को स्वर्गरथ का लोकार्पण किया।

समाजसेवी अग्रवाल परिवार द्वारा वैशाली नगर भिलाई के सेवार्थ विधायक रिकेश सेन की अपील पर स्वर्ग रथ वाहन भेंट किया गया। जिसका लाभ भिलाईवासी वैशाली नगर विधायक कार्यालय में सूचना देकर ले सकेंगे।

विधायक रिकेश सेन ने जन-सेवा के लिए 'स्वर्ग रथ' सुविधा आज भिलाइयंस को समर्पित करते हुए कहा कि अग्रवाल परिवार के सहयोग से अब भिलाई के प्रमुख मुक्तिधामों के लिए यह वाहन उपलब्ध रहेगा।

वैशाली नगर विधानसभा में विभिन्न आयोजनों के लिए फिल्टर्ड वाटर, फ्री ब्लड टेस्ट, श्रीराम रसोई, वेंटिलेटर एम्बुलेंस, हेलमेट और कंबल बैंक सुविधा प्रारंभ करने के बाद विधायक रिकेश सेन ने आज 'स्वर्ग रथ' सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वैशाली नगर भिलाई के लोगों को यह सेवा वो समर्पित कर रहे हैं।

श्री सेन ने बताया कि 10 अगस्त अपने जन्मदिन पर उन्होंने बुके-केक लाने से मना करते हुए अपील की थी कि सक्षम लोग अगर मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो चिकित्सा से संबंधित उपकरण, खेल सामाग्री आदि दें ताकि इन्हें जरूरतमंदों तक वो पहुंचा सकें। नतीजतन विधायक को तोहफे में दो वेंटिलेटर एम्बुलेंस सहित बड़ी मात्रा में खेल सामग्री मिली। इसका उपयोग भी जनता द्वारा ही किया जाना है।

इसी अपील पर समाजसेवी अग्रवाल परिवार ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की सेवार्थ एक स्वर्ग रथ दिया है। जिसे आज जनसेवार्थ भिलाइयंस को वो समर्पित कर रहे हैं। इसका लाभ क्षेत्र के सभी नागरिक उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र और भिलाईवासियों की आवश्यकता पर स्वर्ग रथ विधायक कार्यालय को सूचना देकर लिया जा सकेगा। यह वाहन केवल भिलाई के राम नगर, रिसाली, दुर्ग मुक्तिधाम, छावनी मुक्तिधाम के लिए उपलब्धता के आधार पर जरूरतमंद तक पहुंचेगा। उन्होंने जनसेवार्थ कार्य के लिए अग्रवाल परिवार को धन्यवाद दिया और हरी झंडी दिखा कर जनसेवार्थ स्वर्ग रथ सेवा को समर्पित किया।

बकायादारों को टाइट करने नगर निगम की बड़ी तैयारी

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय द्वारा आज निगम सभागार में विभाग प्रमुखों और जोन आयुक्तों की एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त ने राजस्व वसूली और शहर की बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए।

राजस्व वसूली में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निगम की संपत्तियों (दुकानों) से विधिवत किराया वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जो भूखंड या आवास स्वामी लंबे समय से संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि संपत्ति कर और जल कर समय पर जमा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। करों के माध्यम से प्राप्त राशि से ही शहर के विकास और सुविधाओं में विस्तार संभव होता है। समय पर भुगतान न होने से व्यवस्था सुधारने में बाधा आती है।

शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने कार्यपालन अभियंता सुनील जैन को निर्देशित किया कि पाइपलाइन और पानी टंकियों में आ रही किसी भी तकनीकी समस्या का तत्काल निराकरण करें। शहर के उच्च क्षमता वाले पुराने पानी टंकियों के मरम्मत हेतु विशेषज्ञ टीम से मरम्मत करवाने का निर्देश निगम आयुक्त दिए हैं। उन्होंने सभी जोन आयुक्तों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और आवागमन जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करें।

'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0' के अंतर्गत जिला कलेक्टर ने ली बैठकें, दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं एमसीपीसी के दिशा-निर्देशन में संचालित मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफलता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा जिला न्यायालय के सभागार में तीन पृथक-पृथक महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया।

प्रथम बैठक में जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में अधिवक्ताओं की भूमिका, प्रकरणों को मध्यस्थता हेतु चिन्हित किए जाने, पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों से अवगत कराने तथा अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

द्वितीय बैठक उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के साथ हुई, जिसमें उपभोक्ता विवादों के शीघ्र, सौहार्दपूर्ण एवं सहमति-आधारित निराकरण हेतु मध्यस्थता की उपयोगिता पर चर्चा की गई तथा उपयुक्त प्रकरणों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने की कार्ययोजना पर सहमति बनी।

तृतीय बैठक में मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया गया, जिसमें मध्यस्थता की गुणवत्ता, निष्पक्षता, समयबद्धता तथा व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार किया गया। साथ ही मध्यस्थ अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक प्रकरणों में प्रभावी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि मध्यस्थता न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी, त्वरित एवं मानवीय माध्यम है, जिससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम होता है, बल्कि पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। अभियान की सफलता हेतु सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण सहयोग का वायदा किया।

बीएसपी की 'गिफ्टमिल्क' योजना का तृतीय चरण प्रारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रमुख पोषण आधारित सीएसआर पहल 'गिफ्टमिल्क कार्यक्रम' के तृतीय चरण का शुभारंभ 6 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर कॉन्क्लेव के दौरान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया।

यह कॉन्क्लेव पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका विषय पर एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन) द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के खनन प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बाल कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटना है।

सीएसआर के अंतर्गत क्रियान्वित गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के तृतीय चरण में भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क खदानों के बफर जोन अंतर्गत स्थित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 4,000 बच्चों को विटामिनङ्कए एवं डी से युक्त फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह दूध एनडीडीबी द्वारा प्रबंधित छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे अंतिम छोर तक पोषण पहुंचाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी सुदृढ़ होगी।

कॉन्क्लेव के दौरान लौह अयस्क खदान क्षेत्र के बफर जोन गांवों में दूध वितरण का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित केंद्रीय मंत्रियों द्वारा रावघाट खदान क्षेत्र के विद्यालयों से आए 21 स्कूली बच्चों को मंच पर गिफ्टमिल्क पैकेट वितरित कर कार्यक्रम के अगले चरण का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर सेल की ओर से निदेशक (वित्त) अशोक कुमार पंडा एवं कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन- निगमित कार्यालय) राजीव पांडेय ने संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त सेल-निगमित कार्यालय के मानव संसाधन विभाग से मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा, महाप्रबंधक मलय गोस्वामी, सहायक महाप्रबंधक वीणू बाला सहित बीएसपी के सीएसआर विभाग से महाप्रबंधक मनोज दुबे एवं अन्य उपस्थित थे।

धमधा जनपद पंचायत में हो रहे सर्वाधिक कार्य, 115 में कार्य प्रगति पर

मनरेगा : 294 ग्राम पंचायतों में 49 हजार को रोजगार

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले की 300 ग्राम पंचायतों में से 294 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे 49,126 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इन कार्यों के लिए कुल 1,642 मस्टर रोल जारी किए गए हैं।

जिले के धमधा जनपद पंचायत क्षेत्र में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ 25,298 मजदूरों को रोजगार मिला है तथा 586 मस्टर रोल जारी किए गए हैं। धमधा क्षेत्र की 119 ग्राम पंचायतों में से 115 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कार्य चल रहे हैं।

दूसरे स्थान पर जनपद पंचायत पाटन है, जहाँ 108 ग्राम पंचायतों में 14,997 मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है और 564 मस्टर रोल जारी किए गए हैं। वहीं, जनपद पंचायत दुर्ग की 71 ग्राम पंचायतों में 8,831 मजदूरों को रोजगार मिला है, जिसके लिए 709 मस्टर रोल जारी किए गए हैं।

जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि मजदूरों की मांग के आधार पर गत वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जन-जागरूकता अभियान चलाकर मजदूरों को निरंतर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

मनरेगा के अंतर्गत जिले में आजीविका डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, नाली निर्माण, वृक्षारोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, अमृत सरोवर, सोख पिट, रिचार्ज पिट एवं चेक डेम जैसे विभिन्न रोजगारमूलक निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा एक बड़ा सहारा सिद्ध हो रहा है। खरीफ फसल की खेती-किसानी का कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक मिट्टी के कार्य प्रारंभ किए जाने की मांग भी लगातार सामने आ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

अवैध क्रैशर प्लांट के विरुद्ध मामला दर्ज, जनदर्शन में आया था प्रकरण

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह की संवेदनशीलता के चलते ग्राम पंचायत पतोरा और मुड़पार में अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। विगत सोमवार को आयोजित जनदर्शन में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पतोरा में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अवैध क्रशरों की शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि इन क्रशरों के संचालन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि निर्धारित मानकों की भी अनदेखी की जा रही है।

जनदर्शन में प्राप्त आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल खनिज विभाग को जाँच और कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

इसके बाद खनिज विभाग की टीम ने पतोरा और नजदीकी ग्राम मुड़पार का औचक निरीक्षण किया। जाँच के दौरान पाया गया कि क्रशर संचालक पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग ने छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन भंडारण नियम 2009 एवं एमएम (डीआर) एक्ट 1987 की धारा 21 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रशासन की इस तत्परता से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन और अवैध क्रशर संचालन के विरुद्ध इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना सत्र 2025-26 पर दिशा निर्देश

कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना सत्र 2025-26 के संबंध में सर्व संबंधित प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 12वीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के कुल लक्ष्य विरुद्ध पर्याप्त समय दिये जाने उपरांत भी आवेदन प्राप्त नहीं हुये है, शेष बचे पात्र विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्ति हेतु 30 जनवरी 2026 तक पोर्टल में उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित संस्था सत्यापन का कार्य पूर्ण करें। कक्षा 10वीं एसटी/एससी व कक्षा 12वीं एससी वर्ग के प्राप्त आवेदनों का डी.पीआई स्तर पर पुनः सत्यापन उपरांत प्रेषित करते का निर्देश दिया गया है। 11 जनवरी के पूर्व दावा आपत्ति पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

नीट एग्जाम के सफल आयोजन के लिए समन्वय समिति का गठन

कोरबा। नीट एग्जाम 2026 के सफल संचालन हेतु कोरबा जिलास्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर, जिला कोरबा होंगे। पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोरबा समिति के सदस्य रहेंगे। जिला नोडल अधिकारी (एनटीए) एवं प्राचार्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय को जिला समन्वयक नियुक्त किया गया है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कोरबा को भी समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति नीट परीक्षा 2026 के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों, व्यवस्थाओं और समन्वय को सुनिश्चित करेगी।

चावल उत्सव एवं उपभोक्ता जागरूकता 9 जनवरी तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 2 से 9 जनवरी 2026 तक चावल उत्सव एवं उपभोक्ता जागरूकता के रूप मना रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रजत जयंती सप्ताह में सभी जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकान में रजत जयंती चावल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रजत जयंती चावल उत्सव के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में माह जनवरी का खाद्यान्न वितरण के साथ ही विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ राशनकार्डधारियों एवं आम नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

बस्तर में गोवंश की सुरक्षा को खतरा, उठाए तस्करी और अव्यवस्था के मुद्दे

जगदलपुर। बस्तर संभाग में गोवंश संरक्षण को लेकर हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक संगठन हैप्पी फ्रेंड्स सोशल वेलफेयर सोसायटी (हैप्पी कामधेनु गौशाला) ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गोवंश तस्करी, रेल हादसों में हो रही मौतों और पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संस्था का कहना है कि वह बीते एक दशक से गौसेवा के कार्य में लगी हुई है और वर्तमान में 300 से अधिक गोवंश का संरक्षण एवं उपचार कर रही है। इसके बावजूद, प्रशासनिक निगरानी कमजोर होने के कारण गोवंश तस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है और तस्कर खुलेआम सक्रिय हैं। संस्था के अनुसार, ग्राम पामेला और लोहंडीगुड़ा के साप्ताहिक पशु बाजार धीरे-धीरे अवैध गोवंश तस्करी के प्रमुख अड्डे बनते जा रहे हैं। तस्कर ग्रामीणों को बहकाकर गोवंश की खरीद करते हैं और रात के अंधेरे में उन्हें पार कर देते हैं। संगठन ने मांग की है कि पशु बाजारों में खरीदारों की पहचान अनिवार्य की जाए, एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जाने वाले पशुओं की संख्या तय हो, गोवंश की तत्काल टैगिंग और ऑनलाइन पंजीयन किया जाए।

सौर सुजला ने बदली किस्मत : केंदई की बधानो बनीं आत्मनिर्भर किसान

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। ग्राम केंदई की बधानो बिंझवार आज ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्रगतिशील खेती का जीवंत उदाहरण हैं। पहले उनकी खेती केवल सीमित सिंचाई पर निर्भर थी। बिजली उपलब्ध न होने या डीजल के बढ़ते खर्च के कारण वे खेतों को समय पर पानी नहीं दे पाती थीं। इससे फसल उत्पादन कम होता था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित रहती थी।

स्थिति तब बदली, जब उन्हें सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप का लाभ मिला।

सोलर पंप लगने के बाद उनके खेतों को नियमित और निरंतर पानी मिलना शुरू हुआ। अब वे बिना किसी रुकावट के समय पर सिंचाई कर पाती हैं। परिणामस्वरूप धान के साथ अन्य फसलों का उत्पादन भी बढ़ा। बेहतर सिंचाई से फसल की गुणवत्ता सुधरी और बाजार में उचित मूल्य मिलने लगा।

सोलर पंप ने न केवल डीज़ल खर्च को समाप्त किया, बल्कि समय और मेहनत दोनों बचाए। सिंचाई की

सुविधा पक्की होने से बधानो बिंझवार की खेती अब मुनाफे की खेती बन चुकी है। उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई है और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है।

आज वे गांव की महिलाओं और किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, यह दिखाते हुए कि सही सुविधा और प्रयास से ग्रामीण जीवन में भी बड़ा परिवर्तन संभव है।

सौर सुजला योजना के सकारात्मक प्रभावों का यह उदाहरण बताता है कि यह योजना केवल सिंचाई उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा रही है। जिले में इस वर्ष अब तक 210 किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिससे ग्रामीण कृषि में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

उल्लेखनीय है कि सौर सुजला योजना उन सभी सवालों का जवाब है जो सालों से ग्रामीण तथा दूरस्थ अंचलों को प्रभावित करती रही है। इसमें न पोल का झंझट और न तार का झमेला।

बस्तर के कोने-कोने तक पहुंचेगी शांति और खुशहाली : विजय शर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा आज बीजापुर जिले के अतिसंवेदनशील ग्राम कुटरू पहुंचे, जहां उन्होंने नियद नेल्ला नार के अन्तर्गत सम्मिलित पंचायतों के विकास हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजापुर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आये ग्रामीण जनप्रतिनिधि एवं समाज प्रमुख गायता, सिरहा, पुजारी, बैगा आदि शामिल हुए।

इस दौरान उप उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हिंसा के साथ विकास करना कभी भी संभव नहीं रहा है। आज बस्तर अंचल के कोने कोने में हर गांव में शांति और खुशहाली लाने के लिए शासन पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बस्तर में शांति के लिए आवश्यक है कि माओवादी विचारधारा के प्रभाव में आकर भटके युवा वापस आये और पुनर्वास का रास्ता अपना कर ग्राम और देश के विकास में अपना योगदान दें।

उन्होंने आगे कहा कि शासन द्वारा बस्तर अंचल के सभी ग्रामों के विकास के लिए ग्राम स्तर पर विकास के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। जिसके तहत ग्राम की महिला समूहों और

युवाओं को सक्षम बनाकर स्थानीय वनोपजों के प्रसंस्करण का कार्य गांव में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण वनोपज संग्राहक से उत्पादक और उत्पादक से व्यवसायी बनेंगे और अपने उत्पादों का स्वयं प्रसंस्करण कर वनोपजों का उचित मूल्य भी प्राप्त करेंगे। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए नियद नेल्ला नार योजना शुरू की गई है, जहां स्थानीय कैम्प विकास का केंद्र बन गए हैं और गांव में विकास कार्यों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव गांव में शासकीय योजनाओं की संतृप्तता का कार्य करते हुए हर योजना का लाभ प्रत्येक ग्रामीण को दिलाया जा रहा है।

उन्होंने समाज प्रमुखों से अपील की कि वे जंगलों में माओवादी गतिविधियों में सम्मिलित अपने ग्राम के युवाओं को समझाएं और पुनर्वास कराएं। ऐसे ग्राम जो अपने सभी सदस्यों को मुख्यधारा में लाकर ग्राम को सशस्त्र नक्सल हिंसा से मुक्त घोषित करेंगे, उन ग्रामों में इलवद पंचायत योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर ग्राम पंचायत केतुलनार पेठा, मंगापेठा रानी बोली, अंबेली और दरभा जो नक्सल मुक्त होने के कगार पर है उन्हें नक्सल मुक्त होने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया। ताकि इलवंद गांव? के रूप में उनका विकास किया जा सके।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों स्व उनके ग्रामों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, रोजगार एवं आजीविका संवर्धन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि आज तक उनके ग्रामों में नक्सल गतिविधियों के कारण विकास नहीं पहुंच पाया था पर अब उनके ग्रामों तक सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिससे वे बहुत खुश हैं।

कार्यक्रम में बीजापुर की ग्रामीण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई थी। जिसका अवलोकन करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उनके खाद्य उत्पादों का भी स्वाद लिया और वनोपजों के बेहतर प्रसंस्करण और बाजार उपलब्धता पर चर्चा की। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह एवं संचालक अश्विनी देवांगन, एडीजी नक्सल आपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे, ग्रामों के समाज प्रमुख एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

जीरो टॉलरेंस नीति का असर धरातल भी दिखनी चाहिए

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने प्रतिबद्ध है इसके लिये जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सभी अधिकारी इस नीति को धरातल पर उतारने अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन या लोगों की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सीएमएचओ स्कूल व अस्पतालों का नियमित दौरा कर निरीक्षण करें और कमियों को दुरुस्त करें। शासन स्तर पर कोई मांग हो तो तत्काल प्रस्ताव भेजें, मंजूरी देने में कोई विलम्ब नहीं होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों में विकास कार्य निर्धारित कर प्रस्ताव तैयार करने कहा। इसी तरह नगरीय निकायों में सडक, पानी, बिजली, नाली, साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने वीबीजीरामजी की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिये यह योजना मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के तहत अब ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 125 दिन रोजगार मिलेगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने नगरीय निकायों को परिपत्र

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। सुडा ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी निकायों को इस संबंध में की गई कार्यवाहियों की जानकारी हर महीने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मिशन संचालक को उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

सुडा ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजे परिपत्र में स्वच्छता दीदियों के द्वारा डोर-टू-डोर सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उपायों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

व्यावसायिक क्षेत्रों, साप्ताहिक बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा है। गैर सरकारी संगठनों, रहवासी कल्याण संघों एवं स्वसहायता समूहों की सहभागिता से घर-घर जागरूकता अभियान संचालित करने के लिए भी सभी निकायों को निर्देशित किया गया है।

शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों व विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता अभियान के साथ ही शहर के तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों, मुख्य चौक-चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निस्तारी एवं गैर-निस्तारी तालाबों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सहभागिता से जन-प्रतिनिधियों, धार्मिक गुरूओं, गणमान्य नागरिकों, स्वच्छताग्राहियों, ब्रांड अम्बैसडर्स, एन.जी.ओ. एवं स्वसहायता समूहों को शामिल कर विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

परिपत्र के माध्यम से नगरीय निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए आयोजित सभी कार्यक्रमों को लोकल/क्षेत्रीय मीडिया/नगरीय निकाय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रसारित व पोस्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने निकायों को चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक एवं वेस्ट-टू-आर्ट प्रतियोगिताओं का भी आयोजन विद्यालय स्तर पर करने को कहा गया है।

लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 21 जनवरी से, भारत बनेगा मेजबान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में 'लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में 'इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट' कर रहा है।

चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, भारत में विदेशी मिशन और चुनाव क्षेत्र के शैक्षणिक व व्यावहारिक विशेषज्ञ भाग लेंगे।

यह सम्मेलन वर्ष 2026 के लिए 'इंटरनेशनल आइडिया' के

सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत द्वारा ग्रहण किए जाने पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्धारित एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। सम्मेलन का विषय 'एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीले और विश्व के लिए लोकतंत्र' है।

आईआईआईडीईएम के महानिदेशक, राकेश वर्मा ने इसकी व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे समकालीन चुनौतियों की साझा समझ विकसित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं व नवाचारों के आदान-प्रदान और समाधानों के सह-निर्माण में मदद मिलेगी। इस संबोधन के बाद ट्रिपल आई डीईएम 2026 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया।

ट्रिपल आई डीईएम 2026 प्रतिभागियों को भारत के चुनावी ढांचे, प्रक्रियाओं और तकनीकी नवाचारों से भी परिचित कराएगा, जिन्होंने भारतीय चुनाव को लोकतंत्रों के बीच एक मिसाल बना दिया है।

सम्मेलन में वैश्विक चुनावी विषयों, मॉडल अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर आधारित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

सम्मेलन के दौरान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग, भाग लेने वाले ईएमबी के प्रमुखों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेगा। इस सम्मेलन में 4 आईआईटी, 6 आईआईएम 12 एनएलयू और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भी भागीदारी होगी। इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञों के नेतृत्व में 36 विषयगत समूह विचार-विमर्श में योगदान देंगे।

जशपुर की कृषि सखियों ने ओरमांझी में सीखी आधुनिक खेती पद्धति

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुरनगर। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड में कार्यरत कृषि सखियों के दल का 6 जनवरी 2026 को झारखंड राज्य के रांची जिले अंतर्गत ओरमांझी प्रखंड में कार्यरत प्रसिद्ध एवं सफल किसानों के खेतों में शैक्षणिक परिभ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस परिभ्रमण के दौरान कृषि सखियों ने झारखंड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा सम्मानित कृषक गणशू महतो तथा प्रगतिशील महिला किसान संगीता देवी के खेतों में किए जा रहे उन्नत कृषि कार्यों का गहन अवलोकन किया।

परिभ्रमण के दौरान कृषि सखियों ने गोभी, मटर, मूली, मिर्च सहित विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियों की उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। किसानों द्वारा अपनाई जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे मल्चिंग का महत्व, ऑर्गेनिक खेती की तैयारी, मृदा परीक्षण

की उपयोगिता, उचित उर्वरकों का चयन, मचान खेती, ड्रिप इरीगेशन प्रणाली आदि को प्रत्यक्ष रूप से देखा एवं समझ विकसित की।

यह अभिनव एवं प्रेरणादायक पहल कलेक्टर जशपुर श्री रोहित व्यास के कुशल नेतृत्व में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर श्री अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य विहान अंतर्गत कार्यरत कृषि सखियों को सफल किसानों के अनुभवों से रूबरू कराना, कृषि पद्धतियों, रखरखाव एवं नवाचारों पर विचारों का आदान-प्रदान करना है।

झारखंड सरकार द्वारा सम्मानित कृषक श्री गणशू महतो ग्राम सदमा ओरमांझी झारखंड ने अपने जीवन संघर्ष को साझा करते हुए बताया कि वे कभी 50 प्रतिदिन की नौकरी किया करते थे, किंतु उन्नत कृषि की जानकारी अपनाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आज वे आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख अर्जित कर रहे हैं।

इसी प्रकार प्रगतिशील महिला किसान संगीता देवी ग्राम कच्चू ओरमांझी झारखंड ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने 40 एकड़ जमीन लीज में लेकर वर्तमान में 8 एकड़ भूमि पर सब्जी एवं अन्य फसलों की उन्नत खेती कर लाखों रुपये की वार्षिक आय प्राप्त की। उनके अनुभवों ने महिला कृषकों में आत्मविश्वास एवं आगे बढ़ने की नई ऊर्जा का संचार किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला प्रशासन की इस संयुक्त पहल से निश्चित रूप से जशपुर जिले के किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा महिला कृषकों को सशक्त बनाते हुए उन्हें लखपति दीदी बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा।

भाजपा ने एसआईआर की समस्याओं पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिया ज्ञापन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा, प्रदेश कार्यालय प्रमुख (एसआईआर) मोहन पवार, आईटी सेल के प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लई और वैभव वैष्णव बैरागी ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक पत्र सौंपकर एसआईआर प्रक्रिया में हो रहीं अनियमितताओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि दावा आपत्ति केंद्रों में नियुक्त बीएलओ उपलब्ध नहीं रहते हैं और न ही बीएलओ घर-घर जाकर प्राप्त दावा-आपत्ति का सत्यापन कर रहे हैं। इस कारण प्राप्त दावा आपत्ति का समुचित निराकरण नहीं हो रहा है तथा दावा आपत्ति निराधार रूप से खारिज की जा रही है। इस कारण पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ नहीं पा रहा है तथा अपात्र मतदाताओं का नाम नहीं कट पा रहा है। इसी प्रकार दावा आपत्ति केंद्रों में बीएलओ के पास फॉर्म 6, 7 एवं 8 उपलब्ध नहीं हैं। पत्र में बताया गया कि इस विषय में जब ईआरओ अथवा जिला निर्वाचन अधिकारियों को शिकायत की जाती है तो वो भी ध्यान नहीं देते।

दीपिका की फैन हैं 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की अभिनेत्री सोफी टर्नर, बॉलीवुड में फिल्म करने की जताई इच्छा

बॉलीवुड कलाकारों की हॉलीवुड के एक्टर-एक्ट्रेस के प्रति दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हॉलीवुड में भी अपने देश के कलाकारों की फैन फॉलोइंग कोई कम नहीं है। अब हाल ही में 'गेम ऑफथ्रोन्स' में अपनी भूमिका के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस सोफी टर्नर ने बॉलीवुड स्टार्स दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर की है। हालांकि, इस दौरान जब उनसे शाहरुख और दीपिका में से एक को चुनने को कहा गया, तो एक्ट्रेस मुश्किल में फंस गईं।

फर्स्टपोस्ट के साथ हालिया बातचीत में सोफी टर्नर ने बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के प्रति अपना प्यार जाहिर किया। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर चर्चा के दौरान सोफी ने भारतीय अभिनेताओं खासकर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जमकर प्रशंसा की। हॉलीवुड अभिनेत्री ने दीपिका और शाहरुख की ग्लोबल सिनेमा में योगदान के लिए तारीफ की और उन्हें विदेशों में मिल रही तारीफों पर भी खुशी जताई। इस दौरान जब सोफी से पूछा गया कि शाहरुख और दीपिका में से उनका पसंदीदा कौन है? तो इस सवाल पर सोफी फंस गईं। उन्होंने कहा, 'अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है! मतलब शाहरुख खान तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ही। लेकिन मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद हैं। मुझे लगता है वो कमाल की हैं। साथ ही फिल्मों में मुझे 'आरआरआर' देखना बहुत अच्छा लगा।'

बॉलीवुड फिल्म करना चाहती हैं सोफी

इसके साथ ही सोफी टर्नर ने जल्द ही किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं सचमुच किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहूंगी। मुझे वहां का डांस बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत नजारा होता है और वे बहुत खूबसूरत होते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन इतना शानदार होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमने कभी किसी हॉलीवुड फिल्म सेट पर ऐसा कुछ देखा होगा।

प्रियंका की शादी में भारत आईं थीं सोफी

सोफी टर्नर ने अभी तक किसी भी भारतीय सिनेमा में काम नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने 2018 में अपने पूर्व बहनोई निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की शादी के जश्न के लिए भारत का दौरा किया था। इस समारोह में बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ-साथ वैश्विक हस्तियां भी शामिल हुईं थीं। सोफी टर्नर प्राइम वीडियो की छह-एपिसोड वाली थ्रिलर सीरीज 'स्टील' में नजर आएंगी। यह सीरीज 21 जनवरी से स्ट्रीम करेगी।

मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती कोई फिल्म', तापसी पन्नू ने बताया कैसे करती हैं फिल्मों का चयन

अभिनेत्री तापसी पन्नू अभिनय के अलावा अपने बेबाक बयानों को लेकर भी पहचानी जाती हैं। वो अक्सर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती रहती हैं। अब तापसी पन्नू ने अपने करियर को लेकर बात की और बताया कि कैसे कई फ्लॉप के बाद उन्हें अपने करियर की राह मिली। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कोई फिल्म चुनते वक्त उनके लिए क्या बात सबसे मायने रखती है।

बातचीत के दौरान तापसी पन्नू ने लगातार फ्लॉप फिल्मों और दिल टूटने के बाद अपनी असली पहचान की खोज के बारे में खुलकर बात की। तापसी ने कहा कि मुझे अपनी असली पहचान पाने के लिए लगातार कई फ्लॉप फिल्मों और दिल तोड़ने वाले अनुभवों से गुजरना पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि मैं उन फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हूं, जिनमें मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से उस चीज से जुड़ा होता है जिसे मैं पेश कर रही हूं। उस प्रोजेक्ट का दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव होता है। इसलिए अब मैं सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनती हूं। मैं शायद उन प्रोजेक्ट्स को नहीं चुनती जो मेरे बैंक खाते को बढ़ाएं, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरी आर्टिस्टिक क्षमता को निखारें। एक ऐसा नया रास्ता बनाएं जिस पर ज्यादा लोग नहीं चलते।

अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करती हैं तापसी

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और भूमिकाएं चुनीं जो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रहीं। हालांकि, तापसी द्वारा लिए गए कुछ अलग तरह के काम और किरदारों ने उन्हें सफलता दिलाई। तब से वह पारंपरिक फॉर्मूले की परवाह किए बिना अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपना खुद का एल्गोरिदम बनाया है।

तापसी पन्नू का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो तापसी आखिरी बार साल 2024 में आई फिल्म 'खेल खेल में' नजर आई थीं। यह मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म थी। इसके बाद अब उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में 'वो लड़की है कहां?', 'गांधारी' और 'दुर्गा' जैसी फिल्में शामिल हैं। वो 'दुर्गा' की शूटिंग भी शुरू कर चुकी हैं।

47 साल की हुईं बिपाशा बसु, काजोल से लेकर सोनम कपूर तक ने किया बर्थ डे विश, दीया मिर्जा ने लुटाया प्यार

बिपाशा बसु के जन्मदिन पर पति करण सिंह ग्रोवर ने एक प्यार भरी पोस्ट शेयर की, एक्ट्रेस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। करण के अलावा बिपाशा की दोस्त दीया मिर्जा और एक्ट्रेस काजोल, सोनम कपूर ने भी उन्हें बधाई दी है। जानिए, बिपाशा के लिए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इन एक्ट्रेसेस ने क्या लिखा?

काजोल लंबे वक्त से बिपाशा को जानती हैं। दुर्गा पूजा पर दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। काजोल ने भी बिपाशा को जन्मदिन की बधाई दी है। वह लिखती हैं, 'इस खूबसूरत लड़की को जन्मदिन की शुभकामनाएं।' काजोल ने बिपाशा की एक सुंदर सी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह लाल रंग की साड़ी पहने हैं।

सोनम कपूर ने किया बर्थ डे विश

सोनम कपूर और बिपाशा बसु ने साल 2011 में एक एक्शन मूवी 'प्लेयर्स' में साथ काम किया था। यह दोनों अच्छी दोस्त हैं। सोनम कपूर ने बिपाशा के साथ वाली एक पुरानी फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है। साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी है।

दीया मिर्जा ने बिपाशा पर लुटाया प्यार

दीया मिर्जा, बिपाशा बसु की पुरानी दोस्त हैं। उन्होंने अपनी दोस्त पर जन्मदिन पर खूब प्यार लुटाया है। दीया मिर्जा एक इंस्टाग्राम पोस्ट करती हुए लिखती हैं, 'हैप्पी बर्थ डे' बंगाली ब्यूटी। तुम बहुत अच्छी और प्यारी हो। यह साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो।'

सामंथा की नई तेलुगु फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज, एक्शन अंदाज में दिखीं

साउथ एक्ट्रेस सामंथा की आने वाली तेलुगु फिल्म 'मां इंटी बंगारम' है। इस फिल्म को उनके पति और प्रोड्यूसर राज निदिमोरु ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की निर्देशक नंदिनी रेड्डी हैं। बुधवार को सामंथा की इस फिल्म का पहला पोस्टर लुक सामने आया है।

तेलुगु फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के पोस्टर में सामंथा ने साड़ी पहनी है। उनका किरदार गुस्से में नजर आ रहा है। वह बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के इस लुक पर उनके फैंस ने भी रिएक्शन दिया और उनको सराहा है।

फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के पोस्टर रिलीज के साथ ही मेकर्स ने इसके टीजर, ट्रेलर की तारीख भी शेयर की है। इस फिल्म का टीजर दर्शकों को 9 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगा। इसके रिलीज का समय भी बताया गया है। 9 जनवरी को सुबह दस बजे फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का टीजर सामंथा के फैंस देख पाएंगे।

सामंथा इस वेब सीरीज में भी आएंगी नजर

'सिटाडेल हनी बनी' और 'फैमिली मैन 2' जैसी हिट वेब सीरीज करने के बाद सामंथा एक और वेब सीरीज का हिस्सा बनी हैं। इस वेब सीरीज को भी राज निदिमोरु प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीरीज का नाम 'रक्त ब्रह्मांड' है। यह एक एक्शन सीरीज होगी।

पुरानी साड़ियां फेंकने की बजाय उनका इन 5 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

अगर आपके पास पुरानी साड़ियां रखी हुई हैं तो उन्हें फेंकने की बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करें। ये साड़ियां न केवल आपकी यादों का हिस्सा होती हैं, बल्कि उन्हें नए और अलग तरीकों से उपयोग करके आप अपनी फैशन स्टाइल या घर की सजावट का हिस्सा बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और रचनात्मक आइडियाज देंगे, जिनसे आप अपनी पुरानी साड़ियों को नए अंदाज में पहन सकती हैं।

कुर्ती बनाएं

पुरानी साड़ियों से आप सुंदर कुर्ती बना सकती हैं। बस साड़ी के पल्लू को काटकर कुर्ती का आकार दें और उसे सिलाई करें। इसके लिए आप अपनी पसंदीदा डिजाइन चुन सकती हैं, जैसे कि कॉलर कम कुर्ती, बोट नेक या वी नेक। इस तरह आप अपनी पुरानी साड़ियों को नया रूप देकर उन्हें फैशन में शामिल कर सकती हैं। इससे न केवल आपकी पुरानी साड़ी का सही उपयोग होगा, बल्कि आप एक नया और अलग अंदाज भी पा सकेंगी।

बिस्तर की चादर बनाएं

पुरानी साड़ियों से आप बिस्तर की चादर भी बना सकती हैं। इसके लिए आप दो या तीन साड़ियों को मिलाकर एक बड़ी चादर बना सकती हैं, जिसमें तकिए के कवर भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह आपके बेडरूम को मिलेगा एक नया और रंग-बिरंगा रूप, जो आपके कमरे को सजाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप इस चादर सेट को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा कर सकती हैं।

पर्दे बनाएं

पुरानी साड़ियों से आप अपने घर के लिए सुंदर पर्दे भी बना सकती हैं। बस साड़ी को लंबाई में काटकर उसमें छेद करके रस्सी डाल दें ताकि वह आसानी से लटक सके। इसके अलावा आप चाहें तो पर्दों पर कुछ कढ़ाई या कढ़ाई वाले पैच भी लगा सकती हैं, जिससे वे और भी आकर्षक दिखें। इस तरह आपके घर को मिलेगा एक नया और रंग-बिरंगा रूप, जो आपके कमरे को सजाने में मदद करेगा।

टेबल कवर बनाएं

अगर आपके घर में कोई टेबल कवर नहीं है तो आप उसे भी अपनी पुरानी साड़ियों से बना सकती हैं। इसके लिए बस साड़ी को टेबल के आकार में काट लें और उसकी किनारी को ठीक कर लें ताकि वह फटी न दिखे। इस तरह आपकी टेबल को मिलेगा एक नया और आकर्षक रूप, जो आपके कमरे को सजाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो टेबल कवर पर कुछ कढ़ाई या पैच भी लगा सकती हैं।

बैग बनाएं

आप अपनी पुरानी साड़ियों से बैग भी बना सकती हैं। इसके लिए साड़ी को काटकर बैग का आकार दें और उसमें हैंडल लगा दें। आप चाहें तो बैग पर कुछ कढ़ाई या पैच भी लगा सकती हैं, जिससे वह और भी आकर्षक दिखेगा देखने वाले तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। इस तरह आप अपनी पुरानी साड़ियों को नए अंदाज में इस्तेमाल करके उन्हें बेहतरीन तरीके से फैशन में शामिल कर सकती हैं।

खास खबर

वित्त मंत्री चौधरी ने मंत्री केदार कश्यप के विभागों के बजट तैयारियों पर की चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में उनके विभागों के बजट की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। इनमें मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना और चरण पादुका योजना शामिल हैं। इसके साथ ही वन प्रबंधन समितियों और वनोपज से विभिन्न उत्पाद तैयार कर राजस्व बढ़ाने के विषय पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मंत्री द्वय ने धान उपार्जन केंद्रों में सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की। साथ ही वनांचल क्षेत्रों में आजीविका और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर सार्थक सुझाव दिए गए। बैठक में पंचायत स्तर पर माइक्रो एटीएम की बेहतर व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रावधान करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से सूरजपुर जिले में रजत जयंती चावल उत्सव का किया जा रहा आयोजन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूरजपुर जिले में रजत जयंती चावल उत्सव जन-उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित यह उत्सव 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक जिलेभर में संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं जनहितकारी बनाना है। उत्सव के तहत प्रतापपुर क्षेत्र के मरहटा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सूरजपुर शहर में नगर पालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल की उपस्थिति में चावल उत्सव संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त जिले की विभिन्न पंचायतों एवं समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में पार्षदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुनादी, बैनर एवं सूचना पटों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। यह उत्सव केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्षों की उपलब्धियों तथा राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने का भी सशक्त माध्यम है।

साप्ताहिक बाजार बकावंड में पहुंचा यातायात रथ, जागरूक किया ग्रामीणों को

जगदलपुर। बस्तर एसपी शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान जिले में चल रहा है। इस के तहत यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग द्वारा प्रतिदिन यातायात जागरूकता रथ को जिला अंतर्गत विभिन्न कस्बों एवं ग्रामों के साप्ताहिक बाजार में भेजकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में यातयात जगदलपुर द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार बकावंड में यातायात जागरुकता वाहन में पहुंच कर बस,आटो,टैक्सी, पिकअप में यातायात जागरूकता से संबंधित पोस्टर पंपलेट चिपका कर एवं आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बनेगा सिरकट्टी धाम : मुख्यमंत्री

श्रीरामजानकी मंदिर के शिखर पर लहराई धर्मध्वजाः मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की समृद्धि की कामना की

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गरियाबंद जिले के सिरकट्टी धाम आश्रम स्थित श्रीरामजानकी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की तथा मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्मध्वजा की स्थापना की। उन्होंने आश्रम को सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताते हुए आश्रम परिसर में समरसता भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में जो आध्यात्मिक चेतना का वातावरण निर्मित हुआ है, उसी की अखंड धारा का विस्तार आज सिरकट्टी धाम में धर्मध्वजा स्थापना के रूप में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऋषि-मुनियों, साधु-संतों और आध्यात्मिक परंपराओं की पवित्र भूमि है। हमें धर्म को केवल आस्था के रूप में नहीं, बल्कि कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल का अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया। दंडकारण्य के रूप में विख्यात अबूझमाड़ का विशाल जंगल कभी नक्सल समस्या से प्रभावित क्षेत्र था, जो आज तेजी से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 39 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निशुल्क तीर्थयात्रा कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना के अंतर्गत भी अब तक पांच हजार से अधिक श्रद्धालु लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास का कार्य भी निरंतर प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि भोरमदेव क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है तथा रतनपुर के विकास के लिए भी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजिम कल्प-कुंभ का आयोजन भी इस बार भव्य स्वरूप में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रीरामजानकी मंदिर का भव्य स्वरूप जनसहभागिता का अनुपम उदाहरण है। लगभग 22 हजार परिवारों के सहयोग से लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह मंदिर बीते 10 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। राजस्थान के शिल्पियों द्वारा पारंपरिक शैली में बिना सीमेंट और छड़ के उपयोग के निर्मित इस मंदिर की आयु लगभग एक हजार वर्ष आंकी गई है। उन्होंने मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की आस्था और एकजुटता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने धर्मध्वजा रोहण को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल परंपरागत ध्वजारोहण नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में धर्म, अध्यात्म और सामाजिक समरसता की स्थापना का प्रतीक है।

केबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि हम सभी के लिए सिरकट्टी धाम में धर्मध्वजा की स्थापना देखना अलौकिक अनुभव है। कार्यक्रम में सिरकट्टी आश्रम के महामंडलेश्वर महंत संत गोवर्धन शरण व्यास ने स्वागत उद्बोधन में सिरकट्टी आश्रम की स्थापना और महत्व पर जानकारी दी।

इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक सर्वश्री रोहित साहू, दीपेश साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, अनेक जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न स्थानों से आए संत-महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित थे।

बस्तर अब बदल रहा है-शांति, विश्वास और विकास की ओर तेजी से बढ़ता नया बस्तर : मुख्यमंत्री साय

सुकमा में 64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए किया आत्मसमर्पण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले में ?64 लाख के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह केवल सुरक्षा मोर्चे पर उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास और संवाद की जीत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में लागू संतुलित सुरक्षा रणनीति और संवेदनशील पुनर्वास नीति का प्रत्यक्ष परिणाम अब दिखाई दे रहा है। पूना मार्गेम ङ्क पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने उन युवाओं के जीवन में नई आशा जगाई है, जो कभी नक्सलवाद के भ्रम जाल में भटक गए थे। लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविर, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और सुदूर अंचलों तक शासन की सीधी पहुँच ने बस्तर की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आज बस्तर में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आवाज़ गूंज रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सरकार के दरवाज़े हमेशा खुले हैं। सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि नक्सल समस्या का स्थायी समाधान सुरक्षा, विकास और विश्वास की त्रयी में निहित है। मुख्यमंत्री ने शेष माओवादी साथियों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि वे शांति, परिवार और प्रगति का रास्ता चुनें। राज्य सरकार उनकी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर आज शांति की दिशा में निर्णायक क़दम बढ़ा चुका है और हर आत्मसमर्पण के साथ नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और अधिक मज़बूत हो रहा है।

जशपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था सुचारू किसानों को मिल रहा सीधा लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में जशपुर जिले में धान खरीदी का कार्य पूरी तरह व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की निरंतर आवक बनी हुई है। शासन की किसान-हितैषी नीतियों एवं पारदर्शी व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव अब ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। धान खरीदी केंद्र में अपनी उपज बेचने पहुंचे ग्राम बसरूपपुर निवासी किसान श्री कृष्णा यादव ने बताया कि उन्हें केंद्र में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिताजी के नाम से टोकन तुंहर हाथ मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन लिया गया, जिससे निर्धारित तिथि पर केंद्र पहुंचकर बिना किसी प्रतीक्षा के धान की बिक्री संभव हो सकी। श्री यादव ने कहा कि धान खरीदी केंद्र में समय पर नया और साफ-सुथरा बारदाना उपलब्ध कराया गया तथा धान तौल भी समय पर पूरी की गई। चलते न केवल समय की बचत हुई, बल्कि धान की बिक्री भी सहज और पारदर्शी ढंग से हो पाई। किसान यादव ने शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल टोकन प्रणाली एवं सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने ज़िला अस्पताल बलौदा बाजार का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया उन्होंने जिला अस्पताल स्थित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को भारत सरकार के नेशनल क्वॉलिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत क्वॉलिटी सर्टिफिकेट मिलने पर बधाई दी।

श्री जायसवाल ने जिला अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर ,मातृ शिशु अस्पताल ,फिजियोथेरेपी सेंटर का निरीक्षण किया साथ ही मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल -चाल जाना उन्होंने संस्थागत प्रसव में हुई बढ़ोतरी के लिए जिले में हो रहे काम की सराहना की और 50 बिस्तर मातृशिशु अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने मुरुम तालाब के पास एक इंटीग्रेटेड यूनिट के निर्माण की बात भी कही जिसमे योग,नेचुरोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज की व्यवस्था ,सियान क्लिनिक इत्यादि की सुविधा होगी।

स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में यहाँ प्रतिमाह 450 से अधिक प्रसव हो रहे हैं । जिनमें से 200 सिजेरियन प्रसव हैं। इसके अलावा यहाँ प्रतिमाह 300 डायलेसिस हो रहे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ली समीक्षा बैठक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित तीसरे बजट की तैयारियों के तहत मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट निर्माण संबंधी एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने की।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत पंचायत संचालनालय, ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा इकाइयों द्वारा प्रस्तुत बजट मांग प्रस्तावों पर क्रमवार चर्चा करते हुए उनकी उपयोगिता और प्राथमिकताओं की गहन समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान व्यवहारिक एवं प्रभावी होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, आवास निर्माण, स्वच्छता अभियानों तथा आजीविका से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाएँ।

उन्होंने वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रस्ताव निर्माण एवं क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने नवीन योजना प्रारम्भ कर आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाली महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं एवं लखपति दीदियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विभागीय बजट केवल व्यय तक सीमित न होकर ठोस परिणाम देने वाला होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित समाधान, क्षमता संवर्धन और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को अधिक सक्षम एवं पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने प्रत्येक योजना के साथ स्पष्ट लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धियाँ और लागत एवं लाभ का आकलन अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शर्मा ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्ययोजना पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट गांवों में आत्मनिर्भरता, बुनियादी सुविधाओं की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सचिव भीम सिंह, पंचायत संचालक प्रियंका महोबिया, संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक अश्विनी देवांगन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ को दी बधाईः मुख्यमंत्री साय ने आभार व्यक्त किया, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प दोहराया

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडड्र्स का प्रमाणन प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में नड्डा ने उल्लेख किया कि रायपुर IPHL देश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला बन गई है, जिसे यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की विश्वसनीय एवं क्वालिटी-अश्योर्ड डायग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और रायपुर जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनविश्वास को मजबूत किया है और सेवा-प्रदाय के नए मानक स्थापित किए हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने आगे कहा कि IPHL की स्थापना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मिशन पूरे देश में स्वास्थ्य निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क और आपदा तैयारी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन का मूल उद्देश्य गुणवत्ता-सुनिश्चित, अस्पताल-विशिष्ट एवं रोग-विशिष्ट प्रयोगशाला निदान उपलब्ध कराना है। रायपुर IPHL को प्रदान किया गया यह प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रयोगशाला ने अपने मानव संसाधन, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत अधो संरचना का सफलतापूर्वक एकीकरण करते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त किया है।

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि वह रायपुर मॉडल को श्रेष्ठ अभ्यास (बेस्ट प्रैक्टिस) के रूप में अपनाते हुए राज्य के अन्य जिलों और क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रयोगशाला एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं का निरंतर विस्तार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रौद्योगिकी-सक्षम और मानक-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को भी दर्शाती है। यह प्रमाणन संस्थागत परिपक्वता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता आश्वासन की सुदृढ़ होती संस्कृति का परिचायक है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि रायपुर IPHL को प्राप्त NQAS प्रमाणन छत्तीसगढ़ की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि राज्य में प्रयोगशाला सेवाओं के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक उपकरणों और मजबूत अवसंरचना के क्षेत्र में सतत एवं परिणाममूलक सुधार किए गए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि यह प्रमाणन केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों, लैब तकनीशियनों, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला अस्पताल रायपुर की समर्पित टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के अन्य जिलों में भी IPHL को इसी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध, सटीक और विश्वसनीय जांच सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने पुनः आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार और गुणवत्ता संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवर्तन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुदृढ़ करेगा।

जशपुर पुलिस ने तस्करों के चंगुल से छुड़ाए 20 गो वंश, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार

ऑपरेशन शंखनाद के तहत अब तक 144 प्रकरणों में 239 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार कर

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2024 से गौ तस्करी के खिलाफविशेष अभियान ऑपरेशन शंखनाद चलाया जा रहा है, जिसके तहत जशपुर पुलिस निरंतर गौ तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में जशपुर पुलिस को गत दो दिनों में, सिटी कोतवाली जशपुर व थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत अलग अलग मामलों में 20 नग गौ वंशों को मुक्त कराने में सफलता मिली है, व तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप को भी जप्त किया गया है, साथ ही एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।

बता दें जशपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शंखनाद जारी तिथि से अब तक 144 प्रकरणों में जहां 1400 से अधिक गौ वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है, वहीं 239 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जशपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करी में प्रयुक्त 70 वाहनों को भी जप्त किया गया है, जिनमें से 24 वाहनों को राजसात किया जा चुका है , शेष वाहनों की राजसात प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है।

6 जनवरी की शाम करीबन 04.00 बजे सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबीर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ग्राम डूमरटोली के जंगल के रास्ते काफी संख्या में गौ वंशों को बेरहमी पूर्वक मारते पीटते हुए, पैदल झारखंड राज्य की ओर ले जा रहा है। मुखबिर के बताए स्थान डूमरटोली जंगल में जाकर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति 10 नग गौ वंशों को बेरहमी पूर्वक पीटते हुए, पैदल हांक कर जल्दी जल्दी ले जा रहा था। पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेरा बंदी कर गौ वंशों को सकुशल बरामद किया गया था। पुलिस को आता देख संदिग्ध गौ तस्कर जंगल का फायदा उठा कर फरार हो गया था, पुलिस के द्वारा फरार आरोपी को चिन्हित कर लिया गया था, जिसकी पहचान ग्राम डूमरटोली निवासी अजीत राम उम्र 38 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा उक्त फरार संदिग्ध आरोपी अजीत राम को उसके घर में दबिश दे कर हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ पर आरोपी अजीत राम के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि उक्त सभी गौ वंशों को वह गोविंदपुर झारखंड ले जा रहा था, पुलिस के द्वारा उससे गौ वंशों से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया जा सका, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी अजीत राम के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

एक अन्य मामले में जशपुर पुलिस को गत रात्रि में जशपुर क्षेत्र से होकर पिकअप वाहन में गौ तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में रात्रि में संदिग्ध पिकअप वाहन को पकड़ने हेतु जिले की कई थानों की संयुक्त टीम के द्वारा, हाइवे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पिकअप वाहन क्रमांक छ्व॥ -02-क्र्र -4348 आता दिखाई देने पर पुलिस के द्वारा वाहन का पीछा किया जा रहा था। थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत ग्राम पतराटोली के पास गौ तस्कर पिकअप वाहन को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की टीम जब पिकअप वाहन के पास पहुंची और देखा पिकअप में 10 नग गौ वंशों को रस्सी से बांध कर ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस के द्वारा पिकअप में लोड सभी 10 नग गौ वंशों को सकुशल बरामद कर, पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। पिकअप वाहन क्रमांक छ्व॥ -02-क्र्र -4348 को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की पता साजी कर रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा।

मामले में आरोपियों के विरुद्ध थाना लोदाम में छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत सिटी कोतवाली जशपुर व लोदाम क्षेत्रांतर्गत अलग अलग मामलों में 20 नग गौ वंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है, कोतवाली के मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है , वहीं लोदाम क्षेत्रांतर्गत मामले में गौ तस्करी में प्रयुक्त पिकअप को जप्त किया गया है, व फरार आरोपी गौ तस्करों की पातासाजी की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा। गौ तस्करी के खिलाफ जशपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी है।

धान के अवैध परिवहन पर जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक से 400 बोरी धान जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के सीजन में, सरहदी राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने हेतु, धान के बिचौलियों की सक्रियता बढ़ गई है। जिसे रोकने जिला प्रशासन व पुलिस अत्यंत सक्रिय है। प्रशासन व पुलिस की टीम के द्वारा अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरहदी रास्तों पर नाकाबंदी कर निरंतर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। इसी कड़ी में चौकी आरा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा बुधवार की सुबह 05.00 बजे अवैध रूप से धान परिवहन करते दो संदिग्ध ट्रकों से 400 बोरी में कुल 160 क्विंटल धान जब्त कर जिला प्रशासन को सौंपा गया है।

दरअसल 7 जनवरी की सुबह लगभग 5 बजे चौकी आरा पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केतार के पास दो ट्रक क्रमांक CG 04- NW – 7035 व CG 10- BP – 8723 में भारी मात्रा में धान लोड है। जिस पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के द्वारा तत्काल ग्राम केतार के पास उक्त दोनों ट्रकों को घेरा बंदी कर रोका गया। पुलिस के द्वारा जब दोनों संदिग्ध ट्रकों की तलाशी ली गई तो प्रत्येक ट्रक में 200- 200 बोरी में 80- 80 क्विंटल धान लोड मिला।

पुलिस के द्वारा दोनों ट्रकों के ड्राइवरों से पूछताछ की तो ट्रक क्रमांक CG 04- NW – 7035 के ड्राइवर ने अपना नाम लोमन साहू उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम नहरडीह, जिला धमतरी का निवासी होना बताया व ट्रक क्रमांक CG 10- BP – 8723 के चालक ने अपना नाम चन्द्र प्रकाश सोनवानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोहरोदा मस्तूरी जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया। दोनों ट्रक चालकों ने बताया कि वे धान को झारखंड राज्य से लोड कर जशपुर ला रहे थे, पुलिस के द्वारा जब उक्त ट्रक चालकों से धान व मंडी टोकन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग करने पर उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया जा सका। जिस पर पुलिस के द्वारा दोनों ट्रकों से कुल 400 बोरी में 160 क्विंटल धान को जब्त कर कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन को सौंपा गया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस सरहदी राज्यों से अवैध धान परिवहन पर निरंतर निगाह बनाए हुई है, आरा क्षेत्रांतर्गत 02 ट्रक को धान का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया है, जिससे 400 बोरी में 160 क्विंटल धान को जप्त कर, कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अवैध धान परिवहन पर जशपुर पुलिस की कार्यवाही जारी है। जशपुर पुलिस के द्वारा अब तक अवैध धान परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1,960 क्विंटल धान को पकड़ कर कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी आरा सहायक उप निरीक्षक चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक विदवा सागर पैंकरा व आरक्षक बेलसाजर कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ठीक से बाइक चलाने के लिए कहना बुजुर्ग को पड़ा भारी, बदमाश ने पीट-पीटकर ले ली जान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में बुधवार को मामूली सी बात पर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग ने रफड्राइविंग कर रहे युवक को ठीक से बाइक चालाने कहा तो उसे इतना बुरा लगा कि उसने पीट-पीटकर उसकी जान ले ली। इस घटना में बुजुर्ग के साथ वाले उसके एक साथी को भी चोट लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही छावनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार विक्रम राय (66) और सुनील राय एक ही बाइक पर लिंक रोड कैंप-2 से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी बदल से एक युवक तेज रफ्तार बाइक से निकला। यह देख विक्रम राय ने युवक को ठीक से बाइक चलाने कहा। विक्रम राय के इतना कहते ही बाइक सवार युवक आगे जाकर विक्रम राय की बाइक रोक ली और उनसे विवाद करने लगा। विवाद बढ़ा और देखते ही देखते युवक ने हाथ-मुक्कों से बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए सुनील राय पर भी हमला कर दिया। कुछ देर में युवक के कुछ दोस्त भी आ गए आ गए और बुजुर्ग व उसके साथी को पीटकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची। बुजुर्ग व उसके साथी को गंभीर चोट लगी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन विक्रम राय की मौत हो चुकी थी। उसके साथी को चोट आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की।

कुछ ही समय बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सुकांत उर्फ चिरागन सोनकर (19 वर्ष) निवासी लिंक रोड कैंप-2, को हिरासत में ले लिया। छावनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका की हत्या, आरोपी को उम्र कैद

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। हत्या के तीन साल पुराने मामले में कोरबा की एक कोर्ट ने गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या और लाश को नाली में दफनाने वाले आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सोनवानी ने बताया कि हत्या का यह मामला जुलाई 2022 का है। गांव ढेलवाडीह में रहने वाली अंजू उर्फसोनी यादव की गला घोंटकर उसके प्रेमी ने हत्या कर दी थी। सोनी के शव को सागौन बाड़ी ढेलवाडीह के नाली में दफना दिया था। लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। सोनी की खोज खबर लेने के लिए इसकी मां और बहन लगातार प्रयास कर रही थी। परिवार को पता था कि सोनी का प्रेम संबंध गांव ढेलवाडीह में रहने वाले गोपाल उर्फरामगोपाल खड़िया उम्र 29 वर्ष से था। गोपाल और सोनी पति-पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। जब छह माह तक सोनी के बारे में उसके परिवार को जानकारी नहीं मिली तो उसकी मां एक मार्च, 2023 को मानिकपुर चैकी (कोतवाली थाना) पहुंची। उसने बेटी की गुमशुदगी की सूचना देते हुए पुलिस को बताया कि सोनी यादव गोपाल खड़िया के साथ रहती थी। लेकिन गोपाल, सोनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। पूछने पर इधर उधर की बात करके घुमा रहा है।

पुलिस ने पूछताछ के लिए गोपाल खड़िया को हिरासत में लिया। तब खड़िया ने गला घोंटकर सोनी की हत्या करना और शव को देलवाडीह सागौन बाड़ी के नाल में दफनाना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुमति से शव को कब्र से बाहर निकाला। शव से कुछ अंगों को निकालकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया। शव की डीएनए जांच सोनी की मां के डीएनए से कराई गई। जांच में मां-बेटी का डीएनए मैच हुआ। इसके आधार पर शव की पहचान सोनी उर्फअंजू यादव से हुई।

मामले में पुलिस ने मानिकपुर चैकी में गोपाल पर हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया। गोपाल खड़िया को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई कोरबा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत ने गवाह और सबूतों के आधार पर सोनी यादव की हत्या के लिए गोपाल खड़िया को दोषी ठहराया। गोपाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए अर्थ दंड लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि गोपाल को कोर्ट में दोषी ठहराने में सोनी की मां और बहन की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही। सोनी यादव, रामगोपाल के साथ पत्नी की तरह रह रही थी। लेकिन वह सामाजिक रीति रिवाज से रामगोपाल संग शादी करना चाहती थी। इसके लिए रामगोपाल तैयार नहीं था। सोनी के दबाव डालने पर रामगोपाल ने गला घोंटकर हत्या कर दी।

अवैध धान भंडारण, परिवहन करने वाले कोचियों पर कार्यवाही करें : डॉ. संजय कन्नौजे

कलेक्टर ने जारी डीओ के आधार पर समितियों से धान उठाव करने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

सारंगढ़। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जिले में प्रगतिरत कार्यों और मांग तथा शिकायत के समाधान के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में समय सीमा का समीक्षा बैठक लिया। जनशिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति अधिकारियों से पूछकर कलेक्टर ने शीघ्र समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि आवेदक को स्थिति के बारे में समझाएं और लिखित में सूचना दें कि पात्र होने पर संबंधित योजना का लाभ मिलेगा।

इसके लिए पात्र हितग्राही विधिवत आवेदन संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन जमा करें।जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. कन्नौजे ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का दावा आपत्ति सुनवाई और निराकरण कार्य को सभी अधिकारी-कर्मचारी प्राथमिकता से करें। सभी अपने क्लस्टर में मतदाताओं के समस्याओं का निराकरण करें। कलेक्टर ने धान खरीदी का समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी प्रति शनिवार को धान उपार्जन केन्द्र में जाकर स्टॉक का मिलान करें। बफर स्टॉक ज्यादा होने पर मार्कफेड से राइस मिलर्स को जारी डीओ के आधार पर प्राथमिकता से धान उठाव करने के लिए सभी अधिकारी खाद्य, मार्कफेड और सहकारिता संयुक्त रूप से समन्वय में कार्य करें ताकि धान खरीदी कार्य निरंतर सुचारू रूप से संचालित रहे। कलेक्टर ने अपेक्स बैंक के प्रबंधक को कहा कि किसानों के भुगतान कार्य में कोई परेशानी नही आनी चाहिए इसका विशेष ध्यान दें।

कलेक्टर ने सभी उड़नदस्ता टीम को सभी क्षेत्रों में अवैध धान भंडारण, परिवहन करने वाले कोचियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने नगरपालिका परिषद सारंगढ़ सहित जिले के नगर पंचायतों सरसींवा, भटगांव, बिलाईगढ़, बरमकेला और सरिया में अवैध कब्जा को हटाते हुए गली मोहल्ले में साफ सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, प्रकाश व्यवस्था को सुधार करते हुए प्रतिदिन सुबह कार्य निरीक्षण करने के निर्देश दिए।आगामी 26 जनवरी, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना, जिला अस्पताल निर्माण, संयुक्त जिला कार्यालय, स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, पीएमश्री स्कूल निर्माण, अपार आईडी, सरस्वती सायकल वितरण, आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आश्रम छात्रावास के बालक बालिकाओं के हेल्थ चेकअप, एनीमिया जांच, विभिन्न विकास प्राधिकरणों के प्रगति कार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, पीएम किसान सम्मान निधि राजस्व कार्य नक्शा बंटाकन, फौती नामांतरण, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पेंशनर रिपोर्ट, पेंशनरों के बैंक खाता से मोबाइल नंबर सीडिंग, ईऑफिस आदि के कार्यों का समीक्षा कर कलेक्टर ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

खास खबर

शेयर मार्केट में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1.88 करोड़ की ठगी

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जमीन की खरीदी-बिक्री और शेयर मार्केट में रकम ढाई गुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शिवरीनारायण पुलिस ने ठगी करने वाले फरार आरोपी आरोपी उत्तरा कुमार साहू (52 वर्ष) निवासी बिलारी, को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बताया कि पीड़ित राजेश कुमार साहू ने 14 नवंबर 2025 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वर्ष 2023 में भूपेंद्र साहू ने जमीन के कारोबार और अपने बेटे के शेयर मार्केट में काम करने का हवाला देकर निवेश करने पर 25 माह में ढाई गुना रकम लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद अलग-अलग तारीखों में प्रार्थी से करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपये जमा कराए गए, लेकिन न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम लौटाई गई। इस प्रकरण में भूपेंद्र साहू, हिरेंद्र साहू और सुरेंद्र साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि उत्तरा कुमार साहू फरार चल रहा था। जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया पूछताछ में आरोपी ने ठगी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

ड्यूटी में लापरवाहीः थाना करतला के आरक्षक विकास कोसले निलंबित

कोरबा। पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। थाना करतला में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 528 विकास कोसले को सेवा आचरण के उल्लंघन और गंभीर लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को आरक्षक विकास कोसले को डाक वितरण के लिए कोरबा भेजा गया था। ड्यूटी पूर्ण करने के बाद वह 1 जनवरी 2026 को थाना करतला लौटा, लेकिन नियमों के अनुसार रात्रि मुकाम की सूचना न तो थाने को दी और न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को। बिना अनुमति और सूचना के पूरी रात उसके गायब रहने से मामला गंभीर हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरक्षक विभागीय नियमों एवं निर्देशों से भली-भांति परिचित होने के बावजूद लगातार लापरवाही बरत रहा था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता माना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आदेश जारी कर 4 जनवरी 2026 से आरक्षक विकास कोसले को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उसका मुख्यालय रिजर्व केंद्र, कोरबा निर्धारित किया गया है और उसे नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

खेल-खेल में कुएं में डूबा 4 वर्षीय मासूम

कोरबा । जिले के मानिकपुर चैकी क्षेत्र अंतर्गत दादर पीएम आवास के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बस्ती के बच्चों के साथ खेलने निकला 4 वर्षीय बालक प्रशांत यादव कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे दादर बस्ती क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, दादर बस्ती के दामाद मोहल्ले में रहने वाले राजमिस्त्री सावन यादव का बेटा प्रशांत अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने निकला था। खेलते-खेलते सभी बच्चे दादर पीएम आवास के पास स्थित एक सार्वजनिक कुएं के पास पहुँच गए। कुएं की गहराई लगभग 9 फीट बताई जा रही है। कुछ बच्चों को कुएं में नहाते देख प्रशांत भी पानी में उतर गया, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह डूबने लगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950